है। यह एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है और अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। देश की आज़ादी के बाद ही एक विशेषज्ञ के.एल राव की अध्यक्षता में समिति बनी, उसने तत्कालीन सरकार को, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार को सुझाव दिया कि कोसी में बाढ़ रोकने के लिए नेपाल में हाई डैम की स्थापना की जाए। सरकार ने कुछ नहीं किया, तब से लेकर यह समस्या बनी हुई है। इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि उत्तर बिहार को...

श्री उपसभापति : धन्यवाद। ...(**व्यवधान**)... आपके बोलने का समय समाप्त हो गया। आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। ...(**व्यवधान**)...

The following hon. Members associated themselves with the matter raised by the hon. Member, Dr. Bhim Singh: Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri P. Wilson (Tamil Nadu) and Shri Niranjan Bishi (Odisha).

Demand to include the history of the struggle against emergency, in school and college curriculum

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड) **:** धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। मैं आपके माध्यम से यहां एक गम्भीर विषय उठाना चाहता हूं। स्वतंत्रता संग्राम की तरह लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष के इतिहास को भी स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपातकाल भारत के लोकतंत्र का काला अध्याय है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस समय रक्षक ही भक्षक बन गए थे। आज़ादी के बाद इसे लोकतंत्र की दूसरी आज़ादी का नाम भी दिया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1975 में आपातकाल में देश के लोकतंत्र पर कलंक लगाया था। आपातकाल 21 महीने तक चला था, जिसमें नागरिक स्वतंत्रता का हनन, असहमति का दमन और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कुचला गया था। इसके साथ ही हजारों लोगों को बिना कारण के जेलों में ठूंस दिया गया, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए अनेकानेक लोग बलिदान हुए। आपातकाल का वह सियाह कालखंड लोकतांत्रिक सेनानियों के लिए एक दु:स्वप्न है।

श्री उपसभापति : प्लीज़ सीट पर बैठ कर आपस में बात न करें।

श्री नरेश बंसल : आज भी उस दौर को याद करके लोकतांत्रिक सेनानियों की आंखें नम हो जाती हैं। विपक्ष के ज्यादातर नेता खुद आपातकाल की ज्यादतियों का शिकार हुए हैं। देश में 1975 में आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों और दमन का विरोध करने वालों की ओर से की गई...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़ अपनी सीट्स पर बैठें।...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश बंसल : लड़ाई को समझाने वाला एक अध्याय स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे सभी छात्रों को पता चलना चाहिए कि आपातकाल क्या था, इसे कैसे लगाया गया और क्यों लगाया गया? छात्रों को आपातकाल के बारे में जानना चाहिए। उन बलिदानियों के संघर्ष को वर्तमान की और भावी पीढ़ी जान सके, इसलिए आपातकाल की संपूर्ण गाथा बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए।

महोदय, आपातकाल को अगर सही तरीके से पाठ्य पुस्तकों में स्थान दिया जाए, तो लोकतांत्रिक शक्तियों का विकास होगा और प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। सर, भावी पीढ़ी को इस काले अध्याय से परिचित कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम की तरह लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष के इतिहास को भी स्कूल एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। आपातकाल लगाकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान का गला घोंट दिया था। ...(**समय की घंटी**)... ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Naresh Bansal: Dr. Laxmikant Bajpayee (Uttar Pradesh), Shri Brij Lal (Uttar Pradesh), Shrimati Sangeeta (Uttar Pradesh), Shrimati Sadhna Singh (Uttar Pradesh), Dr. Radha Mohan Das Agrawal (Uttar Pradesh), Dr. Sasmit Patra (Odisha), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shrimati Dharmshila Gupta (Bihar), Shri Subhash Chander (Haryana), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Kalpana Saini (Uttarakhand), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shri Devendra Pratap Singh (Chhattisgarh), Ms. Kavita Patidar (Madhya Pradesh), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shri Krishan Lal Panwar (Haryana), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Dr. Bhim Singh (Bihar), Shri Amar Pal Maurya (Uttar Pradesh), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Dr. Bhagwat Karad (Maharashtra), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Dr. Sumer Singh Solanki (Madhya Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shrimati S. Phangnon Konyak (Nagaland), Shri Neeraj Shekhar (Uttar Pradesh), Shri Mithlesh Kumar (Uttar Pradesh), Shri Sadanand Mhalu Shet Tanavade (Goa), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Samik Bhattacharya and Dr. K. Laxman (Uttar Pradesh).

Demand for allocation of Special Economic Zones in the state of Bihar

श्री मनोज कुमार झा (बिहार) : शुक्रिया। उपसभापति महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के लिए आपके समक्ष हूं। देश की प्रगति का खाका उसका ब्लू प्रिंट बिहार जैसे राज्यों की प्रगति के बगैर